

नाबार्ड बैंक के प्रदर्शन मूल्यांकन पर एक अध्ययन

Rakesh Meena^{1*}, Vikram Meena²

¹ Research Scholar, University of Rajasthan

² Research Scholar, Mohanlal Sukhadia University, Udaipur

सार- यह अध्ययन नाबार्ड के प्रदर्शन वश्लेषण के मूल्यांकन के लए कया गया है। नाबार्ड एक वतीय संस्थान है जिसे भारत सरकार द्वारा देश में स्थायी कृष और ग्रामीण वकास को बढ़ावा देने के लए स्थापत कया गया था। नाबार्ड के कार्यो में तकनीकी नवाचारों का प्रचार, वतीय और गैर-वतीय समाधान और संस्थागत वकास शामिल हैं। उपर्युक्त बैंक के वतीय प्रदर्शन का मूल्यांकन पहले पांच वर्षों यानी 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019 के लए कया गया है। डेटा का वश्लेषण व भन्न अनुपातों और वकास वश्लेषण द्वारा कया गया था। इस लेख को समाप्त करने के लए अध्ययन अवध के दौरान बैंक की वतीय सुदृढता संतोषजनक है और बैंक अपनी निधियों द्वारा अपनी पूंजी बढ़ाकर जमा पर उधार देने को कम कर सकता है।

कीवर्ड- वतीय प्रदर्शन, अनुपात वश्लेषण, वकास वश्लेषण, प्रदर्शन, ग्रामीण वकास

-----X-----

1. परिचय

वतीय प्रदर्शन वतीय गतिवध को निष्पादित करने के कार्य का प्रतिनिधत्व करता है। यह इंगत करता है क वतीय उद्देश्यों या लक्ष्यों को कस हद तक पूरा कया गया है। कंपनी के वतीय प्रदर्शन को मौद्रिक रूप में मापा जाता है और इसका उपयोग निर्णय लेने के उद्देश्य से कया जाता है। कसी कंपनी का वतीय प्रदर्शन कसी वशेष अवध के लए कंपनी के वतीय स्वास्थ्य को दर्शाता है। इस प्रकार वतीय प्रदर्शन वश्लेषण वतीय ववरण वश्लेषण के अनुप्रयोगों के माध्यम से एक फर्म की लाभप्रदता और वतीय स्वास्थ्य का व्यवस्थित रूप से उचत, महत्वपूर्ण और तुलनात्मक मूल्यांकन करने की एक प्रक्रया है।[1]

नाबार्ड का इतिहास

नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) की स्थापना 12 जुलाई 1982 को संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। नाबार्ड, एक वकास बैंक के रूप में, ग्रामीण क्षेत्रों में कृष, लघु उद्योग, कुटीर और ग्राम उद्योग, हस्त शल्प और अन्य ग्रामीण शल्प और अन्य संबद्ध आर्थिक गतिवधियों के प्रचार और वकास के लए ऋण और अन्य सुवधाएं प्रदान करने और वनियमत करने के लए अनिवार्य है। एकीकृत ग्रामीण वकास को

बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्ध हासल करने के लए, और उससे जुड़े या प्रासंगक मामलों के लए। नाबार्ड का दृष्टिकोण ग्रामीण समृद्ध को बढ़ावा देना है। मशन समृद्ध हासल करने के लए सहभागी वतीय और गैर-वतीय हस्तक्षेप, नवाचार, प्रौद्योगिकी और संस्थागत वकास के माध्यम से टिकाऊ और समान कृष और ग्रामीण वकास को बढ़ावा देना है। नाबार्ड पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामत्व में है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है, हसनबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है, इसके 31 क्षेत्रीय कार्यालय राज्यों और केंद्र शासत प्रदेशों में स्थित हैं, श्रीनगर में एक प्रकोष्ठ है, भारत के उत्तरी, पूर्वी और दक्षणी भागों में 04 प्रशक्षण प्रतिष्ठान और 414 जिले हैं। जिला स्तर पर कार्यरत वकास प्रबंधक। नाबार्ड के पास 2243 पेशेवर हैं जिन्हें 1130 अन्य कर्मचारियों की सहायता प्राप्त है।[2]

2020-21 के दौरान नए घटनाक्रम

1. एनबीएफसी/एनबीएफसी-एमएफआई के लए आंशक क्रेडिट गारंटी योजना के लए पायलट योजना:

ऋण और पूंजी बाजार से धन जुटाने के लए कृष, एमएसएमई और माइक्रोफाइनेंस क्षेत्रों में ऋण देने वाले

छोटे एनबीएफसी और एनबीएफसी-एमएफआई को सक्षम करने के लिए यह योजना शुरू की गई है।[3]

आंशक ऋण गारंटी नाबार्ड द्वारा अकेले या एक या अधिक वृत्तीय सुवधा एजेंसी के साथ प्रदान की जा सकती है, जो सह-गारंटर के रूप में भी कार्य करेगी और गारंटी जोखिम को साझा करेगी। यह योजना एक पायलट उत्पाद के रूप में शुरू की जाएगी जिसमें मौजूदा बाजार के खलाइयों के साथ एक-एक पायलट के रूप में ₹100 करोड़ के दो लेनदेन किए जाएंगे। इससे जमीनी स्तर पर उच्च ऋण प्रवाह उत्पन्न करने और भव्य में छोटे एनबीएफसी/एनबीएफसी-एमएफआई को नाबार्ड के पुनर्वत ग्राहकों के रूप में वकसत करने में मदद मिलेगी।

2. एनबीएफसी के साथ जुड़ाव - थर्ड पार्टी पूल वश्लेषण

बाजार की स्थितियों और एनबीएफसी से पुनर्वत की मांग को ध्यान में रखते हुए, एनबीएफसी आवेदनों की मूल्यांकन प्रक्रिया को मजबूत किया गया है। एक तृतीय पक्ष पूल वश्लेषण और एनबीएफसी की ताकत की निगरानी मौजूदा निगरानी और मूल्यांकन तंत्र के अतिरिक्त होगा। बाहरी एजेंसियों की रिपोर्ट एनबीएफसी के बारे में व भन्न प्रारंभक चेतावनी संकेतों और एनबीएफसी क्षेत्र के संबंध में बाजार की जानकारी प्रदान करेगी।[4]

3. एसएफबी को एसटी पुनर्वत

कृष कार्य के लिए कसानों को ऋण उपलब्धता, एमएसई क्षेत्रों में कार्यशील पूंजी ऋण, खुदरा व्यापार, छोटे व्यवसायों, पेशेवरों और अन्य असंगठित क्षेत्र को ब्याज की सस्ती दर पर ऋण की सुवधा प्रदान करके वृत्तीय समावेशन में तेजी लाने के लिए, एसएफबी को पात्र संस्था के रूप में शामिल किया गया था एसटी पुनर्वत का लाभ उठाएं। 2020-21 के दौरान नॉर्थ ईस्ट एसएफबी को 49 करोड़ रुपये की राश दी गई है।[5]

2. साहित्य की समीक्षा

अनीता, जेबासेल्वी, (2020) ने खुलासा किया कि ग्रामीण विकास अधिक से अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है, नाबार्ड ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं को छूता है। नाबार्ड रोजगार के नए अवसर पैदा करता है और देश की कम सेवा वाली आबादी को वृत्तीय सहायता प्रदान करता है और बैंकों के कामकाज और वनियमन की संस्था की निगरानी भी करता है। नाबार्ड देश भर के लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए

वरदान रहा है। नाबार्ड ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मौजूदा और भव्य के विकास की रीढ़ है। ग्रामीण क्षेत्र में नाबार्ड द्वारा की गई वृत्तीय पहलों से भारतीय अर्थव्यवस्था के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।[6]

प्रो. डॉ. वंदना के. मश्रा (2015) ने खुलासा किया कि ग्रामीण ऋण संरचना में नाबार्ड की भूमिका का वश्लेषण किया गया है। ग्रामीण ऋण संरचना में प्राथमिकता क्षेत्र शामिल है और इस क्षेत्र को ऋण वतरित करने में जबरदस्त उपलब्धि हासिल की गई है। पूरे अध्ययन के दौरान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋणों का प्रतिशत अधिक रहा। 2013-14 के दौरान कृष ऋण प्रवाह का लक्ष्य 700,000 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था और उपलब्धि 7,23,225 करोड़ रुपये थी, जो लक्ष्य का 103% है। नाबार्ड ने अर्थव्यवस्था में कृष क्षेत्रों के विकास के लिए अल्पकालक और सावध-ऋण के माध्यम से कृष क्षेत्र को धन उधार दिया है।[7]

वीरपॉल कौर मान और अमृतपाल सिंह (2013) ने "कृष क्षेत्र के विकास में नाबार्ड और आरबीआई की भूमिका" नामक एक अध्ययन में वश्लेषण किया कि नाबार्ड ने राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक से पुनर्वतियन कार्यों को ले लिया है। इस अध्ययन से पता चलता है कि नाबार्ड वश्व बैंक और उसके सहयोगी, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन में शामिल है। नाबार्ड बाहरी ऋण के साथ 42 परियोजनाओं के कार्यान्वयन से जुड़ा हुआ है, जिनमें से 38 परियोजनाओं को आईबीआरडी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। [8]

रॉबसन वलयम बी.पी., बर्गे वन फलप (2012) इस अध्ययन का तर्क है कि कनाडा की संघीय सरकार, जिसने 1991 में रियल-रिटर्न बॉन्ड (आरआरबी) जारी करना शुरू किया था, को वर्तमान में करने की योजना से अधिक प्रकार के आरआरबी जारी करने चाहिए। अधिक आरआरबी जारी करने से न केवल निवेशकों की मौजूदा मांग को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकेगा; इसमें अन्य मूल्य-अनुक्रमित उपकरणों के विकास को प्रोत्साहित करने की क्षमता है। कहीं और अनुभव बताता है कि अधिक संघीय आरआरबी अन्य संस्थाओं को मूल्य-सूचकांक ऋण जारी करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, और बिचौलियों को मुद्रास्फीति से जुड़े वार्षिकी के रूप में ऐसे उत्पाद प्रदान करने देंगे, इस प्रकार अधिक कनाडाई बचतकर्ताओं को

जानबूझकर या आकस्मिक मुद्रास्फीति के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं।[9]

जसवीर एस सूरा (2008) अध्ययन से पता चलता है कि भारत में आरआरबी की समग्र स्थिति काफी उत्साहजनक नहीं है। खराब क्रेडिट डेपॉजिट रेशियो अभी भी आरआरबी के बेहतर कामकाज पर संध लगा रहा है। चूंकि आरआरबी को गरीब लोगों के लिए एक बैंक माना जाता है, इस लिए देश के सभी राज्यों में विशेष रूप से अव्यक्त राज्यों में इसकी उपस्थिति चीजों को बेहतर बना सकती है। सरकार को जरूरतमंद ग्रामीण लोगों को ऐसी बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए आरआरबी की शाखाओं को जमीनी स्तर पर फैलाना चाहिए। इसके अलावा, यह बैंक प्रबंधन और प्रायोजित बैंक की जिम्मेदारी है कि वे बैंक के क्रेडिट-जमा अनुपात को बढ़ाने के लिए सुधारात्मक उपाय करें जो ग्रामीण भारत में आरआरबी को प्रासंगिक बना देगा।[10]

कनिका कृष्णा और नैन्सी साहनी (2012) ने "भारत में आरआरबी'एस का वृत्तीय प्रदर्शन मूल्यांकन" प्रकाशित किया, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विकास-पैटर्न और वृत्तीय प्रदर्शन का अध्ययन करना था। किया गया अध्ययन प्रकृति में वर्णनात्मक था और 2006-2012 की अवधि के लिए आरबीआई और नाबार्ड की प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट से डेटा एकत्र किया गया था। समामेलन और कई अन्य कारकों के कारण अध्ययन में आरआरबी के वृत्तीय प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव देखा गया है।[11]

3. अध्ययन का महत्व

व भन्न मामलों में व भन्न लेखांकन उपयोगकर्ताओं के लिए वृत्तीय विश्लेषण का बहुत महत्व है। आय ववरण, बैलेंस शीट और अन्य वृत्तीय डेटा व्यय और आय, लाभ या हानि के स्रोतों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं और व्यवसाय की वृत्तीय स्थिति का आकलन करने में भी मदद करते हैं। नाबार्ड के प्रदर्शन का पता लगाने के लिए वृत्तीय ववरणों का विश्लेषण व भन्न उपकरणों का उपयोग करके किया जाता है।

4. अध्ययन के उद्देश्य

1. नाबार्ड बैंक की उत्पादकता की जांच करना
2. नाबार्ड बैंक की लाभप्रदता के बारे में जानें
3. नाबार्ड बैंक की कार्यकुशलता का परीक्षण करना
4. नाबार्ड बैंक की पूंजी पर्याप्तता का मूल्यांकन करना
5. नाबार्ड बैंक के स्वास्थ्य का मूल्यांकन करना

6. संपत्ति और देनदारियों में परिवर्तन जानने के लिए
7. अचल संपत्ति, स्वयं के फंड और शुद्ध लाभ के विकास प्रतिशत का मूल्यांकन करना।
8. नाबार्ड बैंक के बेहतर प्रदर्शन के लिए सुझाव देना।

5. अनुसंधान पद्धति

रिसर्च डिजाइन: इस स्टडी में क्वांटिटेटिव रिसर्च को अपनाया गया है।

समय अवधि: अध्ययन में नाबार्ड बैंक के वृत्तीय प्रदर्शन की समीक्षा के लिए 2015-2019 से शुरू होने वाली वचाराधीन समयावधि को शामिल किया गया है।

डेटा का प्रकार: इस अध्ययन में उपयोग किए गए डेटा को द्विवृत्तीय स्रोतों जैसे वेबसाइटों, रिपोर्ट, पुस्तकों, पत्रिकाओं, पत्रिकाओं आदि के माध्यम से एकत्र किया गया था।

प्रयुक्त उपकरण: अनुपात विश्लेषण और विकास विश्लेषण।

6. परिणाम और चर्चाएँ

तालिका 1- संपत्ति अनुपात पर रिटर्न

वर्ष	शुद्ध आय	कुल संपत्ति	आरओए
2015	240.32	28580.86	0.84
2016	252.38	31038.49	0.81
2017	264.55	34826.03	0.76
2018	296.19	40664.16	0.73
2019	336.45	48747.04	0.69

तालिका 2- ब्याज कवरेज अनुपात

वर्ष	ईबीआईटी	ब्याज	आईसीआर
2015	342.14	1292.80	0.26
2016	365.27	1543.86	0.24
2017	388.68	1626.79	0.23
2018	435.37	1784.71	0.24
2019	495.93	2219.87	0.22

तालिका 3- शुद्ध ब्याज मार्जिन अनुपात

वर्ष	शुद्ध ब्याज	कुल संपत्ति	शुद्ध ब्याज मार्जिन अनुपात
2015	233.84	28580.86	0.0081
2016	227.31	31038.49	0.0073
2017	280.09	34826.03	0.0080
2018	337.90	40664.16	0.0083
2019	394.31	48747.04	0.0081

ता लका 4 - पूंजी जमा अनुपात

वर्ष	पूंजी	जमा	पूंजी जमा अनुपात
2015	500.00	18645.42	0.027
2016	530.00	18978.63	0.028
2017	670.00	19441.48	0.034
2018	1058.00	21444.99	0.049
2019	1258.00	22414.66	0.056

ता लका 5- क्रेडिट जमा अनुपात

वर्ष	क्रेडिट	जमा	क्रेडिट जमा अनुपात
2015	24589.94	18645.42	131.88
2016	26049.34	18978.63	137.26
2017	30495.51	19441.48	156.86
2018	35211.05	21444.99	164.19
2019	43027.26	22414.66	191.96

ता लका 6- अचल संपत्तियों की वृद्धि

वर्ष	निश्चित संपत्ति	वृद्धि %
2015	32.52	-Ve
2016	35.25	8.39
2017	39.08	10.87
2018	47.12	20.57
2019	50.58	7.34

ता लका 7- स्वयं की निधियों की वृद्धि

वर्ष	स्वयं के फंड (राजधानी और आरक्षण)	वृद्धि %
2015	2460.09	12.56
2016	2742.60	11.48
2017	3147.09	14.75
2018	3831.11	21.73
2019	4367.37	13.99

ता लका 8- Growth of Net Profit

वर्ष	शुद्ध लाभ	वृद्धि %
2015	240.33	29.19
2016	252.38	5.01
2017	264.55	4.82
2018	296.19	11.96
2019	336.45	13.59

7. निष्कर्ष

- वर्ष 2015-2019 से आरओए अनुपात में गरावट का रुझान दिखा रहा है। चूंकि कुल संपत्ति और शुद्ध आय में स्थिर वृद्धि दर है।
- आईसीआर अनुपात वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2019 में गरावट की प्रवृत्ति दर्शाता है।
- एनआईएम अनुपात 2015 और 2019 में समान रहता है। वर्ष 2018 के दौरान इसमें वृद्धि की गई है।
- पूंजी जमा अनुपात में पूंजी के साथ-साथ जमा में वृद्धि के कारण 2015 से 2019 तक बढ़ते रुझान को दर्शाता है।
- जमा पर उधार देने में वृद्धि के कारण वर्ष 2015 से 2019 तक ऋण जमा अनुपात में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई देती है।
- वर्ष 2019 को छोड़कर वर्ष 2015 से 2018 के दौरान अचल संपत्ति की वृद्धि में वृद्धि हुई है।
- नाबाई बैंक के स्वयं के कोष में स्थिर विकास दर है। रिजर्व और सरप्लस में बढ़ोतरी के चलते 2015, 2017, 2018 में इसे बढ़ाया गया है।
- 2015 से 2019 के दौरान अर्जित लाभ में वृद्धि के कारण शुद्ध लाभ की वृद्धि में वृद्धि हुई है।
- 2015 और 2019 के बीच आरओए का माध्य 76% है और माध्य की औसत दर 5.104% है।
- 2015 और 2019 के बीच ICR का माध्य 25% है और माध्य की औसत वृद्धि दर -3.96% है।

- 2015 और 2019 के बीच NIM का माध्य 0.0079% है और माध्य की औसत वृद्धि दर लगभग 0.26% है
- 2015 और 2019 के बीच औसत पूंजी जमा अनुपात 0.039 है और माध्य की औसत वृद्धि दर लगभग 21% है।
- 2015 और 2019 के बीच औसत क्रेडिट जमा अनुपात 156.43 है और माध्य की औसत वृद्धि दर लगभग 10% है।
- 2015 और 2019 के बीच पीएल की औसत दर 277.98 है और औसत औसत दर लगभग 9% है।

8. सुझाव

- बैंक को परिसंपत्त लागत कम करके और राजस्व बढ़ाकर अपना आरओए बढ़ाना होगा।
- बैंक उच्च लागत पर उधार लेने के बजाय अपनी स्वयं की निधियों से अधिक निधियां बना सकता है।
- उन्हें अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए जमा राश पर उधार देना कम करना चाहिए।
- बैंक को अचल संपत्तियों, अपनी निधियों और शुद्ध लाभ की वृद्धि पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

9. सीमाएँ

- व्यवसाय की दक्षता का पता लगाने के लिए अनुपात की तुलना पहले परिणामों या समान व्यवसाय के परिणामों के साथ की जानी चाहिए।
- वृत्तीय स्थिति को इंगित करने के लिए अकेले अनुपात पर्याप्त नहीं हैं।
- खतरों में हेराफेरी हो सकती है जिससे परिणाम गलत हो सकते हैं।
- आदर्श अनुपातों के लिए कोई अंतिम मानक निर्धारित नहीं कर जा सकते हैं।
- यह एक मात्रात्मक विश्लेषण है न कि गुणात्मक विश्लेषण।

10. भविष्य के अनुसंधान के लिए गुंजाइश

आगे के वर्षों में नाबार्ड के वृत्तीय प्रदर्शन का विश्लेषण करके अध्ययन को बढ़ाया जा सकता है, और यह विशेष खंड का विश्लेषण करके किया जा सकता है।

11. निष्कर्ष

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य नाबार्ड बैंक के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है। इस अध्ययन से पता चला कि बैंक ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। बैंक अपने ROA अनुपात, ICR अनुपात और NIM अनुपात में भी सुधार कर सकता है। बैंक अपने स्वयं के कोष से अपनी पूंजी बढ़ाकर जमा पर उधार देने को कम कर सकता है।

12. संदर्भ

1. अनीता, जेबासेल्वी, "ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए नाबार्ड द्वारा की गई वृत्तीय पहल पर एक अध्ययन" ISSN: 0474- 9030 Vol-68-Issue-1-जनवरी-2020।
2. प्रो. डॉ. वंदना के. मश्रा, "प्राथमिकता क्षेत्र ऋण में नाबार्ड द्वारा निभाई गई भूमिका का एक अध्ययन", + जीजेआरए - शोध विश्लेषण के लिए वैश्विक पत्रिका, वॉल्यूम -4, अंक -8, अगस्त- 2015, आईएसएसएन नंबर 2277 - 8160।
3. अवकरण, एन.के. (1999)। द ए वडेंस ऑफ एफ शएंसी गेन: द रोल ऑफ मर्जर एंड द बेनिफिट्स टू द पब्लिक। जर्नल ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस 23, 991-1013। एलंगर, पी। (1994)। कृषि बैंकों के दक्षता विश्लेषण से संभावित लाभ।
4. एलंगर, पी. (1994)। कृषि बैंकों के दक्षता विश्लेषण से संभावित लाभ। अमेरिकन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, 76 (3) पीपी.652-654।
5. गुप्ता, आर.वी. (1998)। वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से कृषि ऋण पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट। भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई।
6. अनीता, जेबासेल्वी, (2020) द ए वडेंस ऑफ एफ शएंसी गेन्स: द रोल ऑफ मर्जर एंड बेनिफिट्स टू द पब्लिक। बैंकिंग और वित्त जर्नल 23, 991-1013।
7. प्रो. डॉ. वंदना के. मश्रा (2015) कृषि बैंकों के दक्षता विश्लेषण से संभावित लाभ। अमेरिकन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, 76 (3) पीपी.652-654।
8. वीरपाल कौर मान और अमृतपाल सिंह (2013)। वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से कृषि ऋण पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट। भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई।

9. रॉबसन व लयम बी.पी., बर्गे वन फ लप (2012) परफॉर्मेंस हाइलाइट्स ऑफ बैंक्स, 1997-98, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, मुंबई।
10. जसवीर एस सूरा (2008) "भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की प्रभावकारिता: एक पारंपरिक विश्लेषण", JIMS-8M, Indian journals.com।
11. कनिका कृष्णा और नैन्सी साहनी (2012) "एस्टडी ऑफ बैंक एफ शंसी टेकंग इनटू अकाउंट रिस्क प्रेफरेंसेस", जर्नल ऑफ बैंकंग एंड फाइनेंस, वॉल्यूम 20, नंबर 6, 1025-45।

Corresponding Author

Rakesh Meena*

Research Scholar, University of Rajasthan